भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3839
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

100-दिवसीय कार्य योजना

3839. श्री यदुवीर वाडियार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा समीक्षा की गई 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं और प्रगति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मैट्रिक्स क्या हैं;

(ख) डाक चौपाल पहल का ब्यौरा क्या है और इस पहल से किस प्रकार रोजगार के अवसर सृजित होंगे;

(ग) इस कार्य योजना के अंतर्गत कितनी नई पहलें शुरू की गई हैं और उनके लक्षित परिणाम क्या हैं और बजट आबंटन कितना है; और

(घ) विशिष्ट आंकड़ों और भौगोलिक वितरण द्वारा समथत कार्यान्वयन और प्रभाव के संदर्भ में प्रथम 100 दिनों में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) डाक विभाग की "100-दिवसीय कार्य योजना" का उद्देश्य निम्नलिखित तीन पहलों के माध्यम से राष्ट्र और इसके नागरिकों के लाभार्थ सेवाओं की डिलिवरी में व्यापक बदलाव लाना और उनकी दक्षता को बढ़ाना है :

(i) **देशभर में 5000 डाक चौपाल :** इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं और नागरिक-केंद्रित सरकारी सेवाओं की सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को सीधे हर नागरिक के द्वार तक पहुंचाना है। इस प्रकार, यह रोजगारपरक योजना नहीं है, बल्कि सेवापरक योजना है। 100 दिवसीय अभियान के दौरान, 16,014 डाक चौपाल आयोजित की गईं, जिनमें कुल 9,31,541 लोगों ने भाग लिया।

(ii) **डाक निर्यात केंद्र (डीएनके) पोर्टल पर 3000 नए निर्यातकों को ऑनबोर्ड करना :** विभाग का लक्ष्य छोटे निर्यातकों की मदद कर ग्रामीण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डीएनके पोर्टल पर 3000 नए निर्यातकों को रजिस्टर और ऑनबोर्ड करना है। यह पहल, विविध प्रकार की अनिवार्य सेवाएं मुहैया कराती है, जिनमें दस्तावेज तैयार करने (डॉक्युमेंटेशन) संबंधी सहायता, बाज़ार संबंधी सूचना, बार-कोडेड लेबल प्रिंटिंग और कागजरहित सीमा-शुल्क क्लीयरेंस आदि शामिल हैं। 'एक जिला - एक उत्पाद' पहल के अनुरूप यह स्कीम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी, जिससे आर्थिक प्रगति और ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। इस संबंध में हुई प्रगति की डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है। 100-दिवसीय अभियान के दौरान, कुल 3400 से अधिक निर्यातक ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं।

(iii) **भारत में मानकीकृत, जियो-कोडेड एड्रैसिंग प्रणाली के विकास के लिए 10 गांवों और 1 शहर में प्रूफ-ऑफ-कॉन्सैप्ट (पीओसी) :** इस पहल का लक्ष्य, सरकारी और निजी सेवाओं की नागरिक केंद्रित डिलिवरी के लिए सरलीकृत एड्रैसिंग समाधान हेतु प्रूफ-ऑफ-कॉन्सैप्ट (पीओसी) प्रदान करना है। 100-दिवसीय अभियान के दौरान, 10 गांवों में पीओसी संबंधी कार्य पूरा किया जा चुका है। विभाग ने 'DIGIPIN' नामक राष्ट्रीय स्तर के एड्रैसिंग ग्रिड का बीटा संस्करण जारी किया है और शीर्ष उद्यमियों, तकनीकी संस्थानों, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के साथ-साथ जनता से फीडबैक के रूप में उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे हैं।

'100-दिवसीय कार्य योजना' के संबंध में हुई प्रगति को मॉनीटर करने के लिए विभागीय डैशबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। डाक विभाग को किए गए बजटीय आबंटन में '100-दिवसीय कार्य योजना' के लिए निधि का प्रावधान किया गया है।

*****